देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित
www.page3news.in
नगर संस्करण वर्ष 14 अंक: 110 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...किशोरावस्था में अपराध सोचनीय

देहरादून, शनिवार, 1 जून 2019

पेज थ्री

PAGE 3 PUBLICATION

मौसम अधिकतम 41.0° न्यूनतम 24.0°

39714.20 | 2 परवेज मुशर्रफ की हालत बिगड़ी | 7 हर टीम को घर जैसा होगा महसूस

अमित शाह देश के नए गृह मंत्री

राजनाथ को रक्षा मंत्रालय, एस.जयशंकर देश के नए विदेश मंत्री

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। जैसा कि पहले से माना जा रहा था कि मोदी सरकार 2.0 में शामिल नए और दिग्गज चेहरे अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हुआ भी वैसा ही। पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद और गुजरात में उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा चुके अमित शाह को देश का नया गृह मंत्री बनाया गया है। वहीं, मोदी सरकार-1 में गृह मंत्री की भूमिका में रहे राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री के तौर पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। नितिन गडकरी को पहले की तरह ही सड़क परिवहन, जबकि अरुण जेटली के सरकार में शामिल न होने की स्थिति में रक्षा मंत्री रहीं निर्मला सीतारमण को इस बार वित्त मंत्री बनाया गया है। मोदी के सरप्राइज मंत्री पूर्व विदेश सचिव एस. जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है। उन्हें अमेरिका, चीन और रूस तीनों महत्वपूर्ण देशों में काम करने का लंबा अनुभव है। उनके शपथ के साथ ही तय माना जा रहा था कि उन्हें विदेश मंत्रालय दिया जा सकता है। जयशंकर को विदेश मंत्री बनाना महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की मिली जिम्मेदारी

भाजपा के नए अध्यक्ष को लेकर अटकलें तेज

संगठन में रहते हुए भी अमित शाह ने कठोर और साहसिक फैसलों की शुरुआत की थी। माना जा रहा है कि मोदी सरकार में वह सामंजस्य की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। यानी उन पर जिम्मेदारी होगी कि वह दूसरे मंत्रालयों के कामकाज पर भी नजर रखें।

सहयोगियों के मंत्रालय बरकरार

खास बात यह है कि आरपीआई के सहयोगी दलों को पिछली बार मिले मंत्रालयों को इस बार भी बरकरार रखा गया है। एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान को इस बार भी उपभोक्ता एवं खाद्य, शिरोमणि अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल को खाद्य प्रसंस्करण, रामदास आठवले को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, शिवसेना के कोटे से आने वाले मंत्री अरविंद सावंत को भारी उद्योग मंत्रालय दिया गया है।

नई कैबिनेट में कुल 57 मंत्री हैं जिनमें भाजपा के 53 जबकि सहयोगी दलों के चार नेताओं को मंत्री बनाया गया है। 20 ऐसे नाम हैं जिन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया है। यह कोशिश हुई है कि हर वर्ग को मौका मिले।

धर्मेंद्र प्रधान
पेट्रोलियम, स्टील, नैचरल गैस

डॉ. महेंद्र नाथ पांडे
स्किल डिवेलपमेंट

गजेंद्र सिंह शेखावत
जल शक्ति

प्रकाश जावड़ेकर
पर्यावरण, सूचना एवं प्रसारण

पीयूष गोयल
रेलवे, वाणिज्य और उद्योग

मुख्तार अब्बास नकवी
अल्पसंख्यक मामले

प्रहलाद जोशी
बीजेपी
कार्य, कोयला, खनन

अरविंद सावंत
भारी उद्योग

गिरिराज सिंह
पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन

नरेंद्र मोदी
कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, सभी नीतिगत मुद्दे, ऐसे सारे विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हैं

राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री

अमित शाह
गृह मंत्री

नितिन गडकरी
सड़क परिवहन

डी वी सदानंद गौड़ा
रसायन एवं उर्वरक

निर्मला सीतारमण
वित्त

डॉ. एस. जयशंकर
विदेश मंत्री

नरेंद्र सिंह तोमर
कृषि एवं ग्रामीण विकास

थावरचंद गहलोत
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

राम विलास पासवान
उपभोक्ता एवं खाद्य

रमेश पोखरियाल निशंक
मानव संसाधन विकास

अर्जुन मुंडा
अनुसूचित जनजाति कल्याण

हरसिमरत कौर बादल
खाद्य प्रसंस्करण

रवि शंकर प्रसाद
कानून एवं संचार

स्मृति इरानी
महिला, बाल विकास एवं कपड़ा

डॉ. हर्षवर्धन
बीजेपी
परिवार कल्याण, विज्ञान

शहीदों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ी

दूसरे कार्यकाल में मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे पहला फैसला शहीदों के बच्चों को दिए जाने वाली स्कॉलरशिप को बढ़ाने के तौर पर किया। शुक्रवार को मोदी 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक में नैशनल डिफेंस फंड के तहत प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीमश में बड़े बदलाव को मंजूरी दी। अब शहीदों के लड़कों को हर महीने 2000 रुपये की जगह 2500 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी तरह लड़कियों को अब 2250 रुपये की जगह प्रति महीने 3000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी।

इतना ही नहीं, स्कॉलरशिप स्कीम के दायरे को बढ़ाते हुए अब इसमें राज्य पुलिस को भी शामिल किया गया है। आतंकी या नक्सली हमले में शहीद हुए राज्य पुलिस के जवानोंध्अफसरों के बच्चों को भी अब स्कॉलरशिप मिलेगी। उन्हें 500 रुपये सालाना स्कॉलरशिप मिलेगी।

इस फैसले की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, श्हमारी सरकार का पहला फैसला उनको समर्पित है, जो भारत की रक्षा करते हैं। नैशनल डिफेंस फंड के तहत पीएम स्कॉलरशिप स्कीम में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें आतंकी या माओवादी हमलों में शहीद हुए पुलिसवालों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाना भी शामिल है।

नैशनल डिफेंस फंड की स्थापना 1962 में की गई थी। फिलहाल इस फंड का इस्तेमाल सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और आरपीएफ के सदस्यों के अलावा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए होता है। इसके तहत दी जाने वाली पीएम स्कॉलरशिप का उद्देश्य शहीदों की विधवाओं और उनके बच्चों के टेक्निकल व पोस्ट-ग्रैजुएट एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना है।

अब हर किसान को मिलेंगे सालाना 6 हजार रुपये

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे, इसके अतिरिक्त किसानों के लिए पेंशन योजना का ऐलान किया गया है। पीएम किसान योजना पहले सिर्फ लघु और सीमांत किसानों के लिए थी। लेकिन बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में इस योजना में सभी किसानों को शामिल करने का वादा किया था, जिस पर पहली ही कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगाई गई। इस योजना का देश के 14.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। 17 जून से संसद सत्र बुलाने का फैसला किया गया है, जो 26 जुलाई तक चलेगा।

त्राल इलाके में सेना ने दो आतंकियों को घेरा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) श्रीनगर। 23 मई को पुलवामा के त्राल इलाके में खूंखार आतंकी जाकिर मूसा के अंत के बाद सेना ने एक बार फिर यहां दो आतंकियों को घेर कर एक बड़ा काउंटर ऑपरेशन शुरू किया है। हिज्बुल मुजाहिदीन का गढ़ कहे जाने वाले त्राल में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।

सूत्रों के मुताबिक, सेना की राष्ट्रीय राइफल्स को शुक्रवार दोपहर त्राल के नानेर इलाके में आतंकी मूवमेंट की जानकारी मिली थी। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसओजी और आर्मी ने यहां संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी बीच यहां आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी की, जिसके बाद काउंटर ऑपरेशन में सेना ने भारी गोलीबारी करते हुए आतंकियों को घेर लिया। इसके बाद इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करते हुए अपनी कार्रवाई शुरू की। त्राल में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और आतंकियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में अंसार गजावत-उल-हिंद के चीफ और मोस्ट वॉन्टेड आतंकी जाकिर मूसा को मार गिराया गया था।

संक्षिप्त समाचार

भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगाः यूएस

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) वॉशिंगटन। ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी है कि रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली 'एस-400' खरीदने के फैसले का अमेरिका और भारत के बीच रक्षा संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि एस-400 सतह से हवा में मार करने में सक्षम रूस की अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। चीन ने रूस से इस प्रणाली की खरीद के लिए 2014 में सबसे पहले समझौता किया था। भारत और रूस के बीच इस प्रणाली की खरीद के लिए पिछले साल अक्टूबर में 5 अरब डॉलर का समझौता हुआ था। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच व्यापक चर्चा के बाद हुआ था।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

चौथी तिमाही में जीडीपी को बड़ा झटका

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। मोदी सरकार के शपथ लेने के दूसरे दिन ही अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बुरी खबर आई है। वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में देश का आर्थिक विकास दर घटकर 6 प्रतिशत से भी नीचे चला गया है। अभी-अभी जारी हुए आंकड़ों के मुताबकि, जनवरी-मार्च तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) महज 5.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। उधर, लेबर सर्वे के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में देश में बेरोजगारी दर भी 6.1: पर रही है।

ग्रोथ रेट 5.8 प्रतिशत पर फिसला

चौथी तिमाही के बेहद कमजोर आंकड़े का असर पूरे वित्त वर्ष की जीडीपी ग्रोथ रेट पर पड़ा जो 7 प्रतिशत से नीचे फिसलकर 6.8 प्रतिशत पर आ गया है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2017-18 की जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.1 प्रतिशत रही थी जबकि पूरे वित्त वर्ष में देश का आर्थिक विकास 7.2 प्रतिशत की दर से हुआ था। यानी, जनवरी-मार्च तिमाही में वित्त वर्ष 2017-18 के मुकाबले वित्त वर्ष 2018-19 में 2.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।